Quest Journals
Journal of Research in Humanities and Social Science
Volume 13 ~ Issue 6 (June 2025) pp: 546-552
ISSN(Online):2321-9467
www.questjournals.org

Research Paper

बिहार में शिक्षा, कौशल और मानव पूंजी निर्माण में विश्व बैंक संचालित कार्यक्रमों का योगदान: निर्धन वर्ग के संदर्भ में मूल्यांकन

मितु कुमारी
विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग,
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

सारांश

बिहार में निर्धन वर्ग के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण के लिए शिक्षा, कौशल-विकास और मानव पूंजी निर्माण तीन परस्पर सम्बद्ध स्तंभ हैं। विश्व बैंक समर्थित कार्यक्रमों ने राज्य में प्राथमिक शिक्षा, शिक्षक-प्रशिक्षण, महिला स्व-सहायता समूह, आजीविका-संवर्धन, डिजिटल वित्तीय समावेशन और कौशल-आधारित रोजगार क्षमता को मजबूत करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रस्तुत शोध-पत्र द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है और इसमें विश्व बैंक के बिहार केंद्रित कार्यक्रमों—District Primary Education Project, Enhancing Teacher Effectiveness in Bihar, JEEViKA, Bihar Transformative Development Project तथा कौशल-विकास से जुड़े राज्य कार्यक्रमों—के योगदान का आर्थिक मूल्यांकन किया गया है। विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि इन कार्यक्रमों ने निर्धन परिवारों में शिक्षा-सुलभता, शिक्षक-प्रशिक्षण, महिला सामूहिकता, वित्तीय पहुँच और कौशल-आधारित आत्मविश्वास को बढ़ाया है; परंतु माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर नामांकन, संक्रमण दर, डिजिटल अवसंरचना और रोजगार-परिणाम अभी भी कमजोर बने हुए हैं। अध्ययन का निष्कर्ष है कि विश्व बैंक समर्थित कार्यक्रमों ने बिहार में मानव पूंजी निर्माण की आधारभूमि तैयार की है, किंतु निर्धन वर्ग के लिए इसके दीर्घकालिक परिणामों को मजबूत करने हेतु शिक्षा-से-कौशल और कौशल-से-रोजगार की कड़ी को अधिक संस्थागत, स्थानीय और परिणाम-आधारित बनाना आवश्यक है।

मुख्य शब्द: *बिहार, विश्व बैंक, शिक्षा, कौशल-विकास, मानव पूंजी, निर्धन वर्ग, JEEViKA, शिक्षक-प्रशिक्षण*

1. प्रस्तावना

आर्थिक विकास के आधुनिक विमर्श में मानव पूंजी को केवल शिक्षा-प्राप्ति तक सीमित नहीं माना जाता, बल्कि इसमें स्वास्थ्य, कौशल, उत्पादक क्षमता, सामाजिक आत्मविश्वास, वित्तीय पहुँच और श्रम-बाजार में भागीदारी की क्षमता भी सम्मिलित होती है। बिहार जैसे राज्य में, जहाँ निर्धनता, ग्रामीण निर्भरता, निम्न औद्योगिकीकरण, श्रम-प्रवासन और सामाजिक वंचना लंबे समय से विकास की प्रमुख चुनौतियाँ रही हैं, वहाँ मानव पूंजी निर्माण का प्रश्न और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है। शिक्षा निर्धन परिवारों को पीढ़ीगत गरीबी से बाहर निकालने का आधार देती है, जबकि कौशल-विकास उस शिक्षा को आय-सृजन और श्रम-बाजार से जोड़ता है। इसी दृष्टि से विश्व बैंक संचालित तथा विश्व बैंक समर्थित कार्यक्रमों ने बिहार में शिक्षा-सुधार, शिक्षक-प्रशिक्षण, ग्रामीण आजीविका, महिला समूहों और कौशल-संवर्धन के माध्यम से निर्धन वर्ग को विकास-प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास किया है [1], [2]। विश्व बैंक समर्थित Enhancing Teacher Effectiveness in Bihar Operation का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को शिक्षक-प्रशिक्षण, शिक्षक-प्रबंधन और उत्तरदायित्व व्यवस्था से जोड़ना था; यह परियोजना 19 May 2015 को स्वीकृत हुई और इसका संशोधित प्रतिबद्धता आकार $159.6 million था।

भारत में नई शिक्षा नीति 2020 ने भी मानव पूंजी निर्माण को समावेशी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और कौशल-उन्मुख सीखने से जोड़ा है। राष्ट्रीय स्तर पर UDISE+ 2023-24 के अनुसार भारत में 24.8 crore विद्यार्थी, 14.72 lakh विद्यालय और 98

lakh शिक्षक स्कूल शिक्षा प्रणाली का हिस्सा हैं; किंतु बिहार की स्थिति इस राष्ट्रीय विस्तार के भीतर विशिष्ट चुनौतियों को सामने रखती है [3]। बिहार में 2023-24 में कुल विद्यालयों की संख्या 94686, कुल शिक्षकों की संख्या 657063 और कुल नामांकन 21020025 था, परंतु GER और संक्रमण दर में राज्य राष्ट्रीय औसत से पीछे था।

इस शोध-पत्र का उद्देश्य यह मूल्यांकन करना है कि बिहार में विश्व बैंक समर्थित कार्यक्रमों ने निर्धन वर्ग के संदर्भ में शिक्षा, कौशल और मानव पूंजी निर्माण में किस प्रकार योगदान दिया है। अध्ययन केवल कार्यक्रमों की उपलब्धियों को सूचीबद्ध नहीं करता, बल्कि उपलब्ध द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर यह भी देखता है कि शिक्षा-सुलभता, शिक्षक-गुणवत्ता, कौशल-प्रशिक्षण, महिला सामूहिकता और रोजगार-संबंधी क्षमता के बीच कैसा संबंध बनता है।

2. अध्ययन की पद्धति

यह अध्ययन पूर्णतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। प्रमुख स्रोतों में विश्व बैंक परियोजना दस्तावेज, विश्व बैंक परिणाम-रिपोर्ट, UDISE+ 2023-24 आँकड़े, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से सम्बद्ध आधिकारिक विवरण, Bihar Skill Development Mission तथा नीति-सम्बंधी उपलब्ध दस्तावेज सम्मिलित हैं। अध्ययन में वर्णनात्मक सांख्यिकी, अनुपात-विश्लेषण, अंतर-विश्लेषण तथा संकेतक-आधारित मूल्यांकन का प्रयोग किया गया है। शिक्षा-क्षेत्र में बिहार और भारत के बीच अंतर को GER gap, dropout differential, transition gap और digital infrastructure gap से मापा गया है। कौशल-क्षेत्र में enrolment-to-certification ratio तथा प्रशिक्षण-केंद्र विस्तार को संकेतक के रूप में लिया गया है।

इस अध्ययन की सीमा यह है कि विश्व बैंक समर्थित कार्यक्रमों का प्रत्यक्ष household-level causal impact सभी कार्यक्रमों के लिए समान रूप से सार्वजनिक रूप में उपलब्ध नहीं है। इसलिए यहाँ कार्यक्रम-विशिष्ट उपलब्धियों को राज्य-स्तरीय शिक्षा एवं कौशल संकेतकों के साथ जोड़कर व्याख्यायित किया गया है। यह पद्धति निर्धन वर्ग के संदर्भ में कार्यक्रमों की दिशा, पहुँच और संरचनात्मक प्रभाव को समझने के लिए उपयुक्त है।

3. बिहार में शिक्षा और मानव पूंजी की पृष्ठभूमि

बिहार में शिक्षा विस्तार का इतिहास सामाजिक न्याय, निर्धनता उन्मूलन और श्रम-गतिशीलता से गहराई से जुड़ा है। प्राथमिक स्तर पर विद्यालयी पहुँच में सुधार हुआ है, परंतु गुणवत्ता, शिक्षक-प्रशिक्षण, डिजिटल संसाधन और माध्यमिक स्तर पर निरंतरता अभी भी बड़ी चुनौती हैं। UDISE+ 2023-24 के अनुसार बिहार में प्राथमिक स्तर का GER 83.4 था, जबकि अखिल भारतीय औसत 93 था। उच्च प्राथमिक स्तर पर बिहार का GER 68.4 था, जबकि राष्ट्रीय औसत 89.7 था। माध्यमिक स्तर पर बिहार का GER 45.6 था, जबकि भारत का औसत 77.4 था; उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बिहार का GER 30 था, जबकि भारत का औसत 56.2 था [3]। ये आँकड़े बताते हैं कि बिहार में शिक्षा का संकट प्राथमिक प्रवेश की तुलना में उच्च कक्षाओं में अधिक तीव्र है।

तालिका 1: बिहार और भारत में चयनित शिक्षा संकेतक, 2023-24

संकेतक	बिहार	भारत	अंतर
प्राथमिक GER	83.4	93.0	-9.6
उच्च प्राथमिक GER	68.4	89.7	-21.3
माध्यमिक GER	45.6	77.4	-31.8
उच्चतर माध्यमिक GER	30.0	56.2	-26.2
प्राथमिक dropout rate	8.9	1.9	+7.0

उच्च प्राथमिक dropout rate	25.9	5.2	+20.7
माध्यमिक dropout rate	25.6	14.1	+11.5
कंप्यूटर सुविधा वाले विद्यालय	19.6%	57.2%	-37.6
इंटरनेट सुविधा वाले विद्यालय	18.5%	53.9%	-35.4

स्रोत: UDISE+ 2023-24 आधारित संकलन [3]।

तालिका 1 से स्पष्ट है कि बिहार में मानव पूंजी निर्माण की प्रमुख बाधा केवल विद्यालय में प्रवेश नहीं है, बल्कि शैक्षणिक निरंतरता, स्तरांतरण और सीखने की गुणवत्ता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर dropout differential +20.7 percentage points है, जो निर्धन परिवारों के बच्चों के लिए विशेष चिंता का विषय है। इसका अर्थ है कि बच्चों का एक बड़ा हिस्सा उस अवस्था से पहले ही शिक्षा से बाहर हो जाता है, जहाँ कौशल-विकास, डिजिटल साक्षरता और व्यावसायिक प्रशिक्षण से जुड़ने की तैयारी शुरू हो सकती थी।

4. विश्व बैंक समर्थित शिक्षा कार्यक्रमों का योगदान

बिहार में विश्व बैंक की शिक्षा-सम्बंधी भूमिका को दो स्तरों पर समझा जा सकता है। पहला, प्राथमिक शिक्षा के विस्तार और संस्थागत ढाँचे से संबंधित ऐतिहासिक परियोजनाएँ; दूसरा, शिक्षक-प्रभावशीलता और शिक्षा-गुणवत्ता पर केंद्रित परियोजनाएँ। District Primary Education Project III ने बिहार और झारखंड में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार की संस्थागत नींव मजबूत करने का प्रयास किया [4]। इसके बाद शिक्षा की चुनौती मात्र access से आगे बढ़कर quality और learning outcomes की चुनौती बन गई।

Enhancing Teacher Effectiveness in Bihar Operation इसी गुणवत्ता-केंद्रित चरण का महत्त्वपूर्ण उदाहरण है। 2015 में भारत सरकार, बिहार सरकार और विश्व बैंक के बीच $250 million के credit agreement पर हस्ताक्षर हुए, जिसका उद्देश्य सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को अधिक qualified, accountable और responsive बनाना था [5]। इस कार्यक्रम से लगभग 450000 शिक्षकों और 21.2 million प्राथमिक विद्यार्थियों को लाभान्वित करने की अपेक्षा की गई थी। विश्व बैंक के विवरण के अनुसार राज्य की teacher training capacity 5000 newly trained teachers per year से कम थी, जबकि आवश्यकता कम से कम 10 गुना अधिक थी; इसलिए परियोजना का केंद्र शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों, ODL certification और continuous professional development पर रखा गया [5]।

इस कार्यक्रम की आर्थिक दृष्टि से विशेषता यह थी कि इसे performance-based financing model के रूप में डिजाइन किया गया। इसका अर्थ यह है कि धनराशि केवल व्यय-आधारित न होकर agreed results की प्राप्ति से जुड़ी थी। बिहार जैसे राज्य में, जहाँ शिक्षा-व्यय का प्रभाव अक्सर कमजोर निगरानी और निष्पादन-समस्याओं के कारण सीमित हो जाता है, वहाँ परिणाम-आधारित वित्तपोषण शासन-सुधार का महत्त्वपूर्ण साधन बन सकता है।

परियोजना-प्रगति के अनुसार बिहार सरकार ने 11000 से अधिक unqualified elementary teachers को open and distance learning के माध्यम से प्रशिक्षित किया, BEST नामक mobile-based attendance app विकसित किया गया और School Score Card application द्वारा School Management Committees को विद्यालयी परिणामों की निगरानी से जोड़ा गया। साथ ही 93 Teacher Education Institutions का infrastructure upgradation पूरा हुआ और 100 अतिरिक्त TEIs पर कार्य प्रारंभ किया गया [2]। ये उपलब्धियाँ केवल शिक्षा-प्रशासन की सुधारात्मक उपलब्धियाँ नहीं हैं, बल्कि निर्धन वर्ग के बच्चों के लिए classroom-level human capital formation की पूर्व-शर्तें हैं।

5. निर्धन वर्ग और शिक्षा-गुणवत्ता: प्रभाव का विश्लेषण

निर्धन परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा का लाभ तभी मानव पूंजी में बदलता है जब विद्यालयी उपस्थिति, शिक्षक-उपलब्धता, सीखने का स्तर और अगली कक्षाओं में संक्रमण मजबूत हो। बिहार में 2023-24 के आँकड़ों से स्पष्ट है कि शिक्षक-

प्रशिक्षण और संस्थागत सुधारों के बावजूद विद्यालयी प्रणाली में गंभीर अंतर बने हुए हैं। प्राथमिक स्तर पर PTR 32 था, जबकि भारत का औसत 21 था। माध्यमिक स्तर पर बिहार का PTR 30 था, जबकि भारत का औसत 16 था। इसका अर्थ है कि शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात में बिहार पर अधिक दबाव है [3]।

मानव पूंजी की दृष्टि से एक सरल शैक्षणिक जोखिम सूचकांक बनाया जा सकता है:

शैक्षणिक जोखिम सूचकांक = GER gap + dropout differential + transition gap

उच्च प्राथमिक से माध्यमिक संक्रमण के लिए बिहार की transition rate 31.5 थी, जबकि भारत की 83.3 थी। अतः transition gap = 51.8 percentage points है। यदि माध्यमिक स्तर पर GER gap 31.8 और dropout differential 11.5 लिया जाए, तो माध्यमिक स्तर का संयुक्त जोखिम सूचकांक:

$$31.8 + 11.5 + 51.8 = 95.1$$

यह उच्च सूचकांक बताता है कि निर्धन वर्ग के बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर मानव पूंजी निर्माण की सबसे कमजोर कड़ी है। प्राथमिक शिक्षा पर निवेश आवश्यक है, परंतु निर्धन परिवारों की आर्थिक गतिशीलता के लिए माध्यमिक शिक्षा, डिजिटल साक्षरता और कौशल-पूर्व तैयारी निर्णायक है। यदि बच्चा माध्यमिक स्तर तक नहीं पहुँचता, तो वह औपचारिक कौशल-प्रशिक्षण, ITI, KYP या रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों में भी सीमित रूप से भाग ले पाता है।

6. कौशल-विकास और विश्व बैंक समर्थित मानव पूंजी ढाँचा

बिहार में कौशल-विकास की प्रमुख चुनौती यह है कि बड़ी संख्या में युवा श्रम-बाजार में प्रवेश करते हैं, परंतु उनके पास औपचारिक कौशल, डिजिटल दक्षता, संप्रेषण क्षमता और रोजगार-साक्षात्कार संबंधी तैयारी का अभाव होता है। Bihar Skill Development Mission का Kushal Yuva Program इसी अंतर को कम करने का प्रयास करता है। इस कार्यक्रम में life skills, Hindi-English communication skills और basic computer literacy को मुख्य घटक बनाया गया है [6]। DME/नीति आयोग के case study विवरण के अनुसार 2019 तक KYP में 1795 approved centres, 7.29 lakh enrolled candidates और 4.83 lakh certified candidates थे।

तालिका 2: Kushal Yuva Program के चयनित संकेतक, 2019

संकेतक	संख्या
स्वीकृत केंद्र	1795
नामांकित उम्मीदवार	7.29 lakh
प्रमाणित उम्मीदवार	4.83 lakh
प्रमाणन अनुपात	66.25%

प्रमाणन अनुपात = 4.83 / 7.29 × 100 = 66.25%

यह प्रमाणन अनुपात बताता है कि नामांकित युवाओं में से लगभग दो-तिहाई प्रशिक्षण पूर्ण कर प्रमाणित हुए। निर्धन वर्ग के संदर्भ में यह महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे युवाओं में पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी, ग्रामीण पृष्ठभूमि और सीमित डिजिटल exposure वाले युवा बड़ी संख्या में हो सकते हैं। फिर भी 33.75% गैर-प्रमाणन अंतर यह संकेत देता है कि प्रशिक्षण पूर्णता, उपस्थिति, सामाजिक बाधाओं, रोजगार से जुड़ाव और migration-related constraints पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

KYP का महत्व इस कारण भी है कि यह केवल तकनीकी प्रशिक्षण नहीं देता, बल्कि employability foundation बनाता है। बिहार जैसे राज्य में जहाँ स्कूल-स्तर पर computer availability 19.6% और internet access 18.5% है, वहाँ basic computer literacy आधारित कौशल-प्रशिक्षण निर्धन वर्ग के युवाओं के लिए डिजिटल असमानता कम करने का माध्यम बन

सकता है [3], [6]। हालांकि, कौशल-प्रशिक्षण की वास्तविक आर्थिक सफलता तभी मानी जाएगी जब certification के बाद placement, self-employment, wage improvement और migration quality में सुधार हो।

7. JEEViKA, महिला समूह और मानव पूंजी निर्माण

बिहार में विश्व बैंक समर्थित JEEViKA कार्यक्रम को केवल आजीविका या microfinance कार्यक्रम मानना पर्याप्त नहीं है। यह निर्धन ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक पूंजी, वित्तीय साक्षरता, सामूहिक निर्णय-क्षमता और परिवार-स्तरीय मानव पूंजी निर्माण से भी जुड़ा है। विश्व बैंक के अनुसार 2008 से 2020 के बीच JEEViKA ने 12 million से अधिक ग्रामीण महिलाओं को 1.03 million self-help groups में संगठित किया [7]। इसके अतिरिक्त World Bank ने Bihar Rural Livelihoods Project और Bihar Transformative Development Project के लिए कुल $453 million IDA support दिया [7]।

JEEViKA-II अर्थात Bihar Transformative Development Project को 2016 में $290 million IDA credit के साथ स्वीकृत किया गया। परियोजना का लक्ष्य household-level income diversification, nutrition और sanitation services की पहुँच बढ़ाना था। इसके लाभार्थियों में 300 blocks और 32 districts की लगभग 5 million गरीब ग्रामीण महिलाएँ शामिल थीं; SC, ST, minorities, EBC और OBC जैसे वंचित समुदायों को कम से कम 60% beneficiary share में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया [8]।

मानव पूंजी निर्माण में JEEViKA का योगदान अप्रत्यक्ष लेकिन गहरा है। जब महिलाएँ SHG से जुड़ती हैं, बचत और ऋण तक पहुँच पाती हैं, पोषण और स्वच्छता व्यवहार सीखती हैं तथा छोटे उद्यमों से आय अर्जित करती हैं, तो परिवार के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल-प्रशिक्षण पर खर्च करने की क्षमता बढ़ती है। निर्धन परिवारों में मानव पूंजी निर्माण अक्सर माँ की वित्तीय भूमिका और निर्णय-क्षमता से जुड़ा होता है। इसलिए JEEViKA शिक्षा-क्षेत्र का प्रत्यक्ष कार्यक्रम न होते हुए भी शिक्षा-निरंतरता और कौशल-निवेश का सामाजिक-आर्थिक आधार बनाता है।

COVID-19 अवधि में JEEViKA की भूमिका ने इसके institutional capital को भी सिद्ध किया। World Bank के अनुसार लॉकडाउन के प्रथम तीन महीनों में JEEViKA women enterprises ने 20.7 million masks बनाए; 58000 village organizations ने 2.4 million अतिरिक्त परिवारों की पहचान public distribution system में inclusion हेतु की; और women banking agents ने तीन महीनों में $38 million के banking transactions किए [7]। ये उपलब्धियाँ बताती हैं कि SHG network निर्धन वर्ग के लिए crisis-resilient human capital infrastructure की तरह कार्य कर सकता है।

8. संकेतक-आधारित समेकित मूल्यांकन

विश्व बैंक समर्थित कार्यक्रमों के प्रभाव को केवल खर्च या परियोजना-आकार से नहीं मापा जा सकता। निर्धन वर्ग के संदर्भ में तीन प्रश्न अधिक महत्त्वपूर्ण हैं: क्या बच्चों की शिक्षा तक पहुँच बढ़ी? क्या शिक्षण की गुणवत्ता और संस्थागत क्षमता सुधरी? क्या शिक्षा के बाद कौशल और आय-सृजन की राह बनी?

तालिका 3: शिक्षा, कौशल और मानव पूंजी पर कार्यक्रमों का संकेतक-आधारित मूल्यांकन

क्षेत्र	कार्यक्रम/हस्तक्षेप	प्रमुख योगदान	शेष चुनौती
प्राथमिक शिक्षा	DPEP, SSA-linked reforms	विद्यालयी पहुँच और संस्थागत ढाँचा	सीखने की गुणवत्ता और retention
शिक्षक-गुणवत्ता	ETEB	शिक्षक-प्रशिक्षण, TEI upgradation, attendance monitoring	PTR और classroom learning gap
कौशल	BSDM/KYP	life skills, communication, digital literacy	certification-to-employment linkage
महिला सशक्तीकरण	JEEViKA	SHG, वित्तीय समावेशन, सामाजिक पूंजी	enterprise scaling और युवा कौशल से integration

निर्धन वर्ग	JEEViKA-II	SC/ST/minority/EBC/OBC households पर विशेष ध्यान	household income से शिक्षा निवेश तक नियमित tracking

इस समेकित मूल्यांकन से स्पष्ट है कि विश्व बैंक समर्थित कार्यक्रमों ने बिहार में मानव पूंजी निर्माण की supply-side संरचना को मजबूत किया है। विद्यालय, शिक्षक, प्रशिक्षण संस्थान, SHG network और skill centres जैसी संस्थागत व्यवस्थाएँ बनी हैं। परंतु demand-side बाधाएँ—गरीबी, बाल श्रम, सामाजिक असमानता, डिजिटल अभाव, अभिभावकीय शिक्षा, किशोरियों की सुरक्षा और रोजगार की अनिश्चितता—अब भी परिणामों को सीमित करती हैं।

9. चर्चा

बिहार में शिक्षा और कौशल विकास का प्रश्न मात्र सामाजिक कल्याण का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह राज्य की दीर्घकालिक उत्पादकता, श्रम-गुणवत्ता और गरीबी-उन्मूलन से जुड़ा आर्थिक प्रश्न है। विश्व बैंक समर्थित कार्यक्रमों ने इस दिशा में तीन प्रकार से योगदान दिया है। पहला, उन्होंने राज्य-व्यवस्था में परिणाम-आधारित कार्यक्रम-प्रबंधन को प्रोत्साहित किया। ETEB में performance-based financing, teacher attendance app और school score card जैसे तंत्र इसी परिवर्तन को दिखाते हैं [2], [5]। दूसरा, JEEViKA ने निर्धन महिलाओं को संगठित कर household-level economic agency को बढ़ाया, जिससे बच्चों की शिक्षा और परिवार की मानव पूंजी पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा [7], [8]। तीसरा, KYP जैसे कार्यक्रमों ने युवाओं को communication, digital literacy और work-readiness से जोड़कर शिक्षा और रोजगार के बीच की दूरी कम करने का प्रयास किया [6]।

फिर भी डेटा यह बताता है कि बिहार में विद्यालयी मानव पूंजी निर्माण की सबसे कमजोर अवस्था upper primary से secondary transition है। जब upper primary to secondary transition rate 31.5 है, तो यह केवल शिक्षा-प्रशासन की कमी नहीं, बल्कि निर्धन परिवारों की आर्थिक विवशता, विद्यालय दूरी, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षक उपलब्धता, किशोरावस्था-संबंधी बाधाओं और स्थानीय रोजगार-कामना से भी जुड़ा हुआ है [3]। इसी कारण विश्व बैंक समर्थित भविष्य के कार्यक्रमों को primary schooling से आगे बढ़कर adolescent education, vocational exposure, girls' secondary retention और school-to-skill transition पर अधिक केंद्रित होना चाहिए।

10. नीति सुझाव

बिहार में निर्धन वर्ग के मानव पूंजी निर्माण को मजबूत करने के लिए पहला सुझाव यह है कि विश्व बैंक समर्थित शिक्षा और आजीविका कार्यक्रमों को एक integrated human capital framework में जोड़ा जाए। JEEViKA households के बच्चों की school attendance, secondary transition और skill enrolment को track किया जा सकता है। इससे परिवार-स्तरीय poverty alleviation और youth-level human capital formation के बीच नीति-सम्बंध स्थापित होगा।

दूसरा, माध्यमिक स्तर पर targeted retention package की आवश्यकता है। जिन blocks में upper primary dropout और transition gap अधिक है, वहाँ छात्रवृत्ति, remedial learning, transport support, digital learning centres और career counselling को जोड़ा जाना चाहिए।

तीसरा, KYP और BSDM को विद्यालयी प्रणाली से पहले जोड़ा जाए। Class 9 से 12 के विद्यार्थियों को communication, digital literacy और employability orientation से परिचित कराने के लिए school-based pre-skill modules विकसित किए जा सकते हैं।

चौथा, teacher effectiveness कार्यक्रमों को learning outcome data से अधिक स्पष्ट रूप से जोड़ा जाना चाहिए। केवल प्रशिक्षण और attendance पर्याप्त नहीं हैं; classroom pedagogy, foundational literacy, numeracy और subject-level achievement को भी परिणाम संकेतक बनाया जाना चाहिए।

पाँचवाँ, JEEViKA SHG network को community education monitoring से जोड़ा जा सकता है। SHG महिलाएँ dropout tracking, किशोरी शिक्षा, digital access और skill mobilization में स्थानीय human capital facilitators की भूमिका निभा सकती हैं।

11. निष्कर्ष

अध्ययन से स्पष्ट है कि बिहार में विश्व बैंक संचालित तथा विश्व बैंक समर्थित कार्यक्रमों ने निर्धन वर्ग के शिक्षा, कौशल और मानव पूंजी निर्माण में बहुस्तरीय योगदान दिया है। ETEB ने शिक्षक-प्रशिक्षण, शिक्षक-प्रबंधन और शिक्षा-गुणवत्ता के संस्थागत आधार को मजबूत किया। JEEViKA और Bihar Transformative Development Project ने गरीब ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर परिवार-स्तरीय सामाजिक और वित्तीय पूंजी का विस्तार किया। KYP और BSDM ने युवाओं को बुनियादी employability skills से जोड़ने का प्रयास किया। इन सबके बावजूद बिहार में माध्यमिक GER, transition rate, dropout rate, digital infrastructure और certification-to-employment linkage अभी भी गंभीर चिंता के विषय हैं।

इसलिए निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि विश्व बैंक समर्थित कार्यक्रमों ने बिहार में मानव पूंजी निर्माण की मजबूत आधारभूमि तैयार की है, परंतु निर्धन वर्ग के लिए इसका पूर्ण आर्थिक लाभ तभी मिलेगा जब शिक्षा, कौशल और आजीविका कार्यक्रमों को अलग-अलग योजनाओं के रूप में नहीं, बल्कि एक सतत जीवन-चक्र आधारित मानव पूंजी रणनीति के रूप में लागू किया जाए।

संदर्भ सूची

1. विश्व बैंक. *भारत—जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना-III: बिहार एवं झारखंड.* दस्तावेज़ एवं प्रतिवेदन. वाशिंगटन, डी.सी.: विश्व बैंक।
2. विश्व बैंक. (2019). *बिहार में शिक्षक प्रभावशीलता संवर्धन कार्यक्रम.* विश्व बैंक संक्षिप्त विवरण. वाशिंगटन, डी.सी.: विश्व बैंक।
3. शिक्षा मंत्रालय / यू-डाइस प्लस. (2025). *बिहार में सार्वभौमिक विद्यालयी शिक्षा: हम कहाँ खड़े हैं? यू-डाइस प्लस 2023–24 आँकड़े.* नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।
4. विश्व बैंक. *भारत—जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना डीपीईपी-III: बिहार एवं झारखंड.* दस्तावेज़ एवं प्रतिवेदन. वाशिंगटन, डी.सी.: विश्व बैंक।
5. विश्व बैंक. (2015, 7 अगस्त). *भारत सरकार और विश्व बैंक ने बिहार में प्राथमिक शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारने हेतु 250 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए.* प्रेस विज्ञप्ति. वाशिंगटन, डी.सी.: विश्व बैंक।
6. विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय, नीति आयोग. (2021). *बिहार में कुशल युवा कार्यक्रम: कौशल विकास का केस अध्ययन.* नई दिल्ली: नीति आयोग, भारत सरकार।
7. विश्व बैंक. (2020). *बिहार राज्य में ग्रामीण विकास हेतु महिला समूहों की शक्ति का विस्तार.* परिणाम-विशेष आलेख. वाशिंगटन, डी.सी.: विश्व बैंक।
8. विश्व बैंक. (2016, 28 जून). *भारत—बिहार परिवर्तनकारी विकास परियोजना "जीविका-II".* ऋण एवं क्रेडिट विवरण. वाशिंगटन, डी.सी.: विश्व बैंक।
9. प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार. (2025, 31 जनवरी). *आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25: शिक्षा एवं मानव पूंजी विकास.* नई दिल्ली: भारत सरकार।